



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 2007/आश्विन 12, 1929

No. 447]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2007/ASVINA 12, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2007

सं. 38/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 642(अ).—जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतस्मिन् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 3 के अंतर्गत, नीचे दी गई सारणी में वर्णित माल पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने (इन पर गैर लेवी समेत) के बारे में सामान्यतया एक प्रथा प्रचलित थी और ऐसे माल पर उत्पाद शुल्क लगाया जाना चाहिए था जो नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, उक्त अधिनियम की धारा 3 के दौरान लेवी मुक्त रह रहे थे :-

सारणी

विवरण	अवधि
(1)	(2)
पोलियस्टर स्टेपल फाइबर, कार्डेड, काम्बड या कटाई के लिए अन्य प्रकार से प्रसंस्कृत, जिसमें कपास मिश्रित हो (इसमें अन्य वस्त्र सामग्री मिश्रित नहीं है) और जिसमें पोलियस्टर स्टेपल फाइबर का अनुपात वजन के हिसाब से कुल फाइबर अवयव का 70 प्रतिशत से कम हो, जिनका विनिर्माण खादी और ग्राम उद्योग आयोग के स्वामित्वाधीन कारखानों द्वारा या खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संगठन द्वारा किया गया हो :	1 मार्च, 1994 से 21 अगस्त, 2002 तक
बशर्ते कि विनिर्माता खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की ओर से प्राधिकृत किसी प्राधिकारी से प्राप्त से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि इन खादी एवं ग्राम उद्योग के स्वामित्व वाले कारखानों में अथवा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित संगठनों में इन रेशों से हाथ द्वारा सूत तैयार किया गया है और इनका प्रयोग केवल पोली वस्त्र तैयार करने में किया जायेगा अर्थात् कोई भी वस्त्र जिसको कपास और पोलियस्टर के मिश्रित सूत से भारत में हथकरघा द्वारा तैयार किया गया है ।	
पोलियस्टर स्टेपल यार्न, जिसमें कपास मिश्रित हो (इसमें अन्य वस्त्र सामग्री मिश्रित न हो) और जिसमें पोलियस्टर स्टेपल फाइबर का अनुपात वजन के हिसाब से कुल फाइबर अवयव के 70 प्रतिशत से कम हो तथा जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के स्वामित्वाधीन किसी कारखाने द्वारा या खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित किसी संगठन द्वारा विनिर्मित अथवा खरीदा गया हो :	1 मार्च, 1994 से 28 फरवरी, 2002 तक
बशर्ते कि विनिर्माता खादी एवं ग्राम उद्योग की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि इस यार्न का प्रयोग केवल पोलीवस्त्र के विनिर्माण में किया गया है अर्थात् इसका प्रयोग ऐसे वस्त्र के विनिर्माण में किया गया है जिसमें कपास और पोलियस्टर मिश्रित है और जिसे भारत में हथकरघा से तैयार किया गया है ।	

2. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11ग के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्देश देती है कि उपरोक्त प्रकार के माल पर लेकिन उक्त रीति के लिए, उक्त अधिनियम के अंतर्गत लगाये जाने योग्य सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क का कालम 2 में वर्णित अवधि तक भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि ऐसे माल के मामले में निर्धारित शर्तें पूरी हों जिन पर उक्त रीति के अनुसार उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा रहा था :

बशर्ते कि इस अधिसूचना के अंतर्गत लाभ तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि इस अधिसूचना की दृष्टि से लाभ के लिए दावा करने वाली इकाई ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयोग किये गये आगत के बारे में लिए गये निविष्टि क्रेडिट यदि कोई हो, को वापस नहीं करती है।

[फा. सं. 52/3/2005-सी एक्स-1]

आशिमा बंसल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2007

No. 38/2007-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 642(E).—Whereas the Central Government is satisfied that a practice was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Act), on goods of the description given in Table below, and that such goods were liable to duty of excise which was not being levied under Section 3 of the said Act according to the said practice, during the period as specified below :—

TABLE

Description	Period
(1)	(2)
Polyester staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning, containing to cotton (not containing any other textile material) and in which the proportion of polyester staple fibre is less than 70 per cent by weight of the total fibre content manufactured by a factory owned by the Khadi and Village Industries Commission or any organisation approved by the Khadi and Village Industries Commission :	1st March, 1994 21st August, 2002
Provided that, the manufacturer produces a certificate from an officer authorised in this behalf by the Khadi and Village Industries Commission, that these fibres have been hand spun into yarns by a factory owned by the Khadi and Village Industries Commission or any organisation approved by the Khadi and Village Industries Commission for use only in the manufacture of Poly Vastra, that is to say, any cloth containing cotton and polyester woven on handloom from yarns hand spun in India.	
Yarn of polyester staple fibre containing cotton (not containing any other textile material) to and in which the proportion of polyester staple fibre is less than 70 per cent, by weight of the total fibre content, manufactured or purchased by a factory owned by the Khadi and Village Industries Commission or any organisation approved by the Khadi and Village Industries Commission :	1st March, 1994 28th February, 2002
Provided that, the manufacturer produces a certificate from an officer authorised in this behalf by the Khadi and Village Industries Commission, that the yarn have been used only in the manufacture of Poly Vastra, that is to say, any cloth containing cotton and polyester woven on handloom from yarns hand spun in India.	

2. Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of duty of excise leviable under the said Act on such goods as described above but for the said practice, shall not be required to be paid for the period detailed in Column 2 above, subject to fulfilment of conditions prescribed in respect of such goods on which the said duty of excise was not being levied during the aforesaid period in accordance with the said practice :

Provided that the benefit under this notification shall not be admissible unless the unit claiming benefit in terms of this notification reverse the input credit, if any taken in respect of inputs used in manufacture of such goods.

[F. No. 52/3/2005-CX. 1]

ASHIMA BANSAL, Under Secy.